POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2014/अंक 08 कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 अगस्त, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अगस्त, 2014 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वित्तमंत्री के रूप में वर्ष 2014-15 का बजट रखा। इसमें बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं और आम नागरिकों के हितों का ध्यान रखा गया है। लेकिन बजट में यह नहीं बताया गया है कि पांच साल में प्रदेश के 15 लाख लोगों को कैसे रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे? यह तभी संभव हो सकता है, जब राज्य का सकल घरेलू उत्पाद मौजूदा स्तर 4.8 लाख करोड़ रुपए से वर्ष 2020 तक 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाए। इसके लिए साफ सुथरी व पारदर्शी रणनीति तैयार करनी होगी।

बजट में बिजली, पानी, स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों पर पूरा ध्यान दिया गया है। खास यह है कि मुख्यमंत्री ने बजट में 'सुशासन कानून' लागू करने का वादा किया है। बजट में जो घोषणाएं की गई हैं वह सभी वर्ग के लोगों को राहत देने वाली है।

कुल मिलाकर इसे अच्छा बजट माना जा सकता है। बजट में की गई सभी घोषणाओं का यदि समय पर सही क्रियान्वयन हो जाता है, तो राजस्थान अन्य राज्यों से बहुत आगे खड़ा नजर आ सकता है। बशर्ते, जनता का पैसा जो राजकोष में आता है वह बेवजह खर्च नहीं हो। इसके लिए प्रशासनिक सुधार बेहद जरूरी है। प्रदेश की जनता भी नई सरकार से यह अपेक्षा रखती है।

केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने भी लोकसभा में आम बजट प्रस्तुत किया। केन्द्र में मोदी सरकार का यह पहला बजट है। लिहाजा, बजट में आम उपभोक्ता को राहत, बुनियादी जरूरतों पर ध्यान, आयकर छूट सीमा बढ़ाना, देश की आर्थिक सेहत सुधारने, कृषि एवं शिक्षा को खास तवज्जो, युवाओं के लिए रोजगार, लघु व नए उद्योगों के लिए फंड, खाद्य सुरक्षा के लिए भंडारण व्यवस्था, महंगाई रोकने व कीमतें स्थिर रखने के लिए फंड, राज्यों के विकास को अहमियत और राजकोषीय सुधार के लिए 'खर्च प्रबन्धन आयोग' का गठन जैसी घोषणाएं कर सभी का दिल जीतने का प्रयास किया गया है।

कुल मिलाकर बजट में कई सुधार साफ नजर आते हैं। अगर सरकार सभी घोषणाओं की समयसीमा तय कर कदम बढ़ाती है, तो यह देश के बहुआयामी विकास और आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम साबित होगा।

सरकारी बजट 'आंकडों का जाल' होता है और आम ग्रामीण सही रूप में उसे समझ नहीं पाता। इसलिए 'ग्राम गदर' में समय-समय पर गांवों से सम्बन्धित बजट घोषणाओं को सरल व तार्किक रूप में प्रकाशित किया जाता है, ताकि ग्रामीणजन इन घोषणाओं के सरकारी अमल पर नजर रख सके और लाभान्वित हो सके।

खेती व किसान को फायदा

प्रदेश के बजट में खरीफ और रबी मौसम में किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त उर्वरक मिले, इसके लिए 28.50 करोड़ रुपए की खाद खरीद कर अग्रिम भंडारण किए जाने का प्रावधान किया गया है। बंजर भूमि को खेती के लायक बनाने के लिए 1392 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे प्रदेश की 3.69 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन खेती के लायक हो सकेगी।

बूंद-बूंद सिंचाई करने वाले किसानों को त्वरित बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। भरतपुर में 1.16 करोड़ रुपए से बीज परीक्षण व कीटनाशी परीक्षण लेब स्थापित की जाएगी। बैंकों के माध्यम से कृषि उपकरणों हेतु लिए गए दीर्घकालीन ऋणों पर पांच फीसदी ब्याज अनुदान देय होगा। 500 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।

सिंचाई के लिए पांच एचपी के सौलर पम्प की स्थापना करने पर सरकार 30 फीसदी अतिरिक्त अनुदान देगी। 18 करोड़ रुपए की लागत से 55 नई मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी। किसानों को लघु अवधि फसली ऋण चार फीसदी रियायती दर पर मिलेगा।

शिक्षा को दी ज्यादा तवज्जो

प्रदेश की 4900 पंचायतों में माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत कर उन्हें उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाया जाएगा। सभी पंचायतों में अंग्रेजी मॉडल स्कूलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्कूली विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान स्कूल एजुकेशन पोर्टल की स्थापना की जाएगी। कृषि संकाय में ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन पर छात्राओं को हर साल 10 हजार के बजाय अब 12 हजार रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी।

ऐसे कॉलेज जहां 5500 से ज्यादा विद्यार्थी हैं, उनका पुनर्गठन कर 15 नए कॉलेज खोले जाएंगे। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा शुरू होगी। सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति दी जाएगी।

प्रदेश में युवाओं को मिलेंगे रोजगार

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने देश के पहले और सबसे बड़े महत्वाकांक्षी आजीविका स्किल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। प्रदेश में इस प्रोजक्ट के लिए 398 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। केन्द्र सरकार ने इसके लिए राजस्थान को प्रथम राज्य के रूप में चुना है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में इस प्रोजेक्ट के तहत इस साल एक लाख ग्रामीण युवाओं को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इनमें 34 हजार महिलाएं होगी।

पहले चरण में चयनित एजेंसियों द्वारा सभी जिलों में कौशल विकास केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले पांच साल में इस प्रोजेक्ट के तहत 15 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।

पंचायतें होंगी सशक्त

पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए दो हजार 74 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। वर्ष 2014-15 में राजनेट परियोजना द्वारा 9177 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक आईटी सर्विस केन्द्र खोला जाएगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा को पंचायत समिति स्तर तक बढ़ाया जाएगा। समस्त पंचायत समितियों पर ग्रामीण युवा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा। ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1800 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

पशु पालन को प्रोत्साहन

प्रदेश में गो-संवर्धन के साथ पंचगव्य के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गोपालन विभाग का गठन किया जाएगा।

पशु चिकित्सा सुविधा के लिए कॉल सेंटर की मार्फत मोबाइल वेटेनरी सेवा टोंक जिले की दो तहसीलों में पायलट बेसिस पर शुरू की जाएगी।

पशुओं की नस्ल सुधार के लिए निजी सहभागिता से पशु नस्ल सुधार योजना प्रारंभ की जाएगी, जो परिणाम आधारित होगी।

स्वास्थ्य सुरक्षा पर खास नजर

पुरानी सरकार की निःशुल्क दवा और जांच योजनाएं जारी रखी गई हैं, इन्हें और बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र सभी परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है।

किसी परिवारजन के बीमार होने पर राजकीय व मान्य निजी चिकित्सालयों में वह भर्ती मरीज के रूप में इलाज करा सकेंगे। सामान्य बीमारियों के लिए प्रति परिवार 30 हजार और गंभीर बीमारियों के लिए तीन लाख तक का बीमा कवर होगा।

नए उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए बजट में 248 करोड़ 17 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 30 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च होंगे। 140.72 करोड़ रुपए बेघर बच्चों व मजदूरों के इलाज के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।

अपना गांव अपना काम योजना

राज्य सरकार अपना गांव अपना काम योजना इसी साल लागू करेगी। इस योजना में लोगों की जरूरत के मुताबिक विकास कार्य होंगे। यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू होगी। योजना के तहत सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए कुछ फीसदी राशि जन सहयोग से जुटाई जाएगी।

शेष राशि राज्य मद से उपलब्ध कराई जाएगी। परिसम्पत्तियों पर दानदाताओं के नाम अंकित करने का प्रावधान भी रखा गया है।

ग्राम विकास के लिए श्री योजना

गांवों में विकास के लिए राज्य सरकार श्री योजना शुरू करेगी। इसके तहत पांच योजनाओं स्वच्छता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, और विद्युत योजनाओं पर एक साथ काम किया जाएगा।

इसी तरह ग्रामीण विकास और रोजगार पैदा करने के लिए गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना फिर शुरू की जाएगी। वर्तमान में जारी ग्रामीण जन भागीदारी योजना को भी इस योजना में समाहित किया जाएगा।

गांवों में 'ग्रामीण गौरव पथ' योजना

-प्रदेश की हर पंचायत में एक सड़क का 'ग्रामीण गौरव पथ' योजना के तहत विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित अन्य योजनाओं में बनने वाली सड़कें बार-बार टूटें नहीं और उनकी उम्र अधिक करने के लिए सीसी रोड़ बनाने का फैसला किया गया है।

नए राजमार्गों व ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत आदि की योजना तैयार कर काम शुरू किया जा चुका है। 250 से 499 तक की आबादी वाले 530 गांवों को विश्व बैंक की सहायता से सड़कों से जोड़ा जाएगा।

पेयजल के लिए लगेंगे आरओ संयंत्र

प्रदेश के 23 हजार 956 गांव-ढ़ाणियों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। शुद्ध पानी के लिए आरओ संयंत्र लगाने की योजना शुरू करने के लिए प्रदेश के बजट में व्यवस्था की गई है। शुरुआत में 800 से अधिक जनसंख्या वाले गांव-ढ़ाणियों में एक हजार आरओ संयंत्र लगाए जाएंगे। आगामी पांच सालों में 5000 आरओ व अन्य तकनीकी संयंत्र लगाए जाएंगे। सभी पंचायत स्तरीय पेयजल योजनाओं को एक बार दुरुस्त कर पंचायतों के सुपुर्द किया जाएगा।

कुपोषण से निपटेंगे आंगनबाड़ी केन्द्र

कुपोषण से निपटने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र में गुणवत्तापूर्ण पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा। इस साल के बजट में 4850 नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण करने व पुराने केन्द्रों की मरम्मत के लिए 276.42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के प्रोत्साहन के लिए मां यशोदा अवॉर्ड एवं उनके मानदेय में वृद्धि करने का भी बजट में प्रावधान है।

समय पर हो अमल

आम लोगों तक आधारभूत सुविधाओं की पहुंच को ध्यान में रख कर आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जाता है। इनमें पानी, बिजली, सड़क, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सेवाएं खासतौर से शामिल हैं। सरकार इन आधारभूत सुविधाओं के लिए बजट में करोड़ों रुपए का प्रावधान करती है।

जनकल्याण की जो भावना बजट के समय दिखाई पड़ती है, वह आमजन के लिए सपना बन कर रह जाती है। क्योंकि, नौकरशाही घोषणाओं पर समयबद्ध रूप से अमल नहीं करती। सरकारी सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण बजट का काफी हिस्सा बीच में ही हजम हो जाता है। इससे सरकार की विश्वसनीयता घटती है। -लक्ष्मण सिंह, ब्यावर

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा

ग्रामीण क्षेत्रों में गठित स्वयं सहायता समूहों से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। वर्ष 2014-15 में 15 हजार स्वयं सहायता समूहों द्वारा दो लाख गरीब महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। नौ हजार गरीब महिला किसानों को उन्नत तकनीक एवं प्रशिक्षण दिला कर उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से 30 से 40 हजार रुपए वार्षिक आय में वृद्धि की जाएगी।

महिलाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर दी जाने वाली छूट बढ़ाई गई है। जनजाति क्षेत्रों में 250 नए मां बाड़ी केन्द्र खोले जाएंगे। अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए 50 कन्या आश्रम छात्रावास खोले जाएंगे। भामाशाह योजना के तहत खोले गए खातों में महिला मुखिया बीपीएल परिवार को 2000 रुपए दो किश्तों में ट्रान्सफर कर जमा कराए जाएंगे।

सुरक्षा के लिए महिलाओं को सेल्फ ट्रेनिंग दी जाएगी। महिला सुरक्षा सलाह केन्द्र चलाने वाले एनजीओ को 30 से 45 हजार रुपए दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में नवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को साइकिल दी जाएगी।

विकलांग बनेंगे आत्म निर्भर

भामाशाह योजना के तहत किए जा रहे सर्वे के साथ विकलांगों का भी सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे में चयनित सभी विकलांगों को आई.डी. नंबर के साथ स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे।

इसके बाद उन्हें विशेष शिविर लगा कर संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के साथ-साथ कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चला कर आत्म निर्भर बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

उन्हें स्वाभिमान से जीने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। निःशक्तजनों को कृत्रिम अंग उपकरण मुहैया कराने के लिए प्रदेश के बजट में 5.85 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

जागो ग्राहक जागो

'कट्स' सेंटर फॉर कन्ज्यूमर एक्शन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (कट्स कार्ट) द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण करने, शिकायतों से संबंधित सूचना एवं सलाह सेवाएं देने के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया हुआ है। कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत या समस्याओं के बारे में स्वयं व्यक्तिश कार्यालय समय में डी-218, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर स्थित कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है अथवा नीचे लिखे फोन, फैक्स व ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रेषित कर सकता है।

CUTS International 1983 2012

फोन: 141-2282823, 2282482, 5133259, फैक्स: 141-4015395
ईमेल: cart@cuts.org, वेबसाइट: www.cuts-international.org/cart

कट्स कार्ट

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर